



**NEERAJ®**

# भारत में राज्य की राजनीति (State Politics in India)

## **B.P.S.E.- 143**

Chapter Wise Reference Book  
Including Many Solved Sample Papers

*Based on*

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

# **I.G.N.O.U.**

**& Various Central, State & Other Open Universities**

*By: Vaishali Gupta*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

*(Publishers of Educational Books)*

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: [info@neerajbooks.com](mailto:info@neerajbooks.com)

Website: [www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

**MRP ₹ 280/-**

## Content

# भारत में राज्य की राजनीति ( State Politics in India )

Question Paper—June-2024 (Solved) .....	1
Question Paper—December-2023 (Solved) .....	1
Question Paper—June-2023 (Solved) .....	1
Question Paper—December-2022 (Solved) .....	1
Question Paper—Exam Held in July-2022 (Solved) .....	1

---

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
--------------	-----------------------------------	-------------

---

### **परिचय ( Introduction )**

1. भारत में राज्य राजनीति का विकास .....	1
( Development of State Politics in India )	
2. विश्लेषण के दृष्टिकोण .....	11
( Approaches to the Study State Politics )	

### **संघवाद ( Federalism )**

3. संघ-राज्य संबंध : विधायी, आर्थिक एवं प्रशासनिक .....	19
( Union-State Relations: Legislative, Economic and Administrative )	
4. राज्य-स्थानीय संबंध .....	30
( State-Local Relations )	
5. राज्य स्वायत्तता .....	43
( State Autonomy )	

<i>S.No.</i>	<i>Chapterwise Reference Book</i>	<i>Page</i>
6.	उप-क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं शासन ..... ( Sub-Regional Autonomy and Governance )	54
<b>विकास और राज्यीय राजनीति ( Development and State Politics )</b>		
7.	राज्य विकास मॉडल ..... ( State Development Models )	62
8.	पलायन ..... ( Migration )	73
<b>दलीय व्यवस्थाएँ और चुनावी राजनीति ( Party Systems and Electoral Politics )</b>		
9.	राज्य दलीय व्यवस्थाएँ ..... ( State Party Systems )	82
10.	चुनावी राजनीति ..... ( Electoral Politics )	93
11.	नेतृत्व ..... ( Leadership )	103
<b>पहचान की राजनीति ( Identity Politics )</b>		
12.	दलित, ओबीसी और महिलाएँ ..... ( Dalit, OBCs and Women )	113
13.	भाषाई और नृजातीय समूह ..... ( Linguistic and Ethenic Groups )	126
14.	क्षेत्र और जनजाति ..... ( Regions and Tribes )	135
15.	नए सामाजिक समूह ..... ( New Social Groups )	146



**Sample Preview  
of the  
Solved  
Sample Question  
Papers**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# QUESTION PAPER

June – 2024

(Solved)

भारत में राज्य की राजनीति  
( State Politics in India )

B.P.S.E.-143

समय : 3 घण्टे ]

] अधिकतम अंक : 100

नोट : इस प्रश्न के दो भाग हैं। कुल पाँच प्रश्नों का उत्तर देने हैं। प्रत्येक भाग में से कम-से-कम दो प्रश्न चुनना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

## भाग-I

प्रश्न 1. भारत में राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-2, पृष्ठ-14, प्रश्न 1

प्रश्न 2. भारत में केन्द्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की योजना का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-23, प्रश्न 1

प्रश्न 3. भारत में उप-क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों के लिए उत्तरदायी कारकों की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-6, पृष्ठ-54, 'क्षेत्रीय स्वायत्तता : मुद्दे एवं चुनौतियाँ'

प्रश्न 4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

(क) जी.एस.टी. परिषद्

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-22, 'जी.एस.टी. परिषद् की संरचना'

(ख) बलवंत राय मेहता समिति

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-4, पृष्ठ-33, प्रश्न 1

## भाग-II

प्रश्न 5. भारत में भाषाई समूहों की राजनीति का परीक्षण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-13, पृष्ठ-127, 'भारत में भाषाई समूह और राजनीति'

प्रश्न 6. पूर्वोत्तर भारत में जातीय राजनीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-14, पृष्ठ-135, 'परिचय' तथा पृष्ठ-141, प्रश्न 4

प्रश्न 7. भारत में जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण की चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-14, पृष्ठ-136, 'भारत में जनजातियों का क्षेत्रीय वितरण'

प्रश्न 8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-

(क) एल.जी.बी.टी.क्यू.

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-15, पृष्ठ-149, 'एल.जी.बी.टी.क्यू. समूह'

(ख) मंडल आयोग

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-12, पृष्ठ-115, 'मंडल आयोग की रिपोर्ट'



# QUESTION PAPER

December – 2023

(Solved)

भारत में राज्य की राजनीति  
( State Politics in India )

B.P.S.E.-143

समय : 3 घण्टे ]

] अधिकतम अंक : 100

नोट : इस प्रश्न के दो भाग हैं। कुल पाँच प्रश्नों का उत्तर देने हैं। प्रत्येक भाग में से कम-से-कम दो प्रश्न चुनना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

## भाग-1

प्रश्न 1. वस्तु एवं सेवा कर ( जी.एस.टी. ) के संदर्भ में केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-24, प्रश्न 3

प्रश्न 2. संघ के कामकाज में संघर्ष के क्षेत्रों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-3, पृष्ठ-27, प्रश्न 2

प्रश्न 3. 'कांग्रेस प्रणाली' के पतन का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-9, पृष्ठ-82, 'परिचय' तथा पृष्ठ-84, प्रश्न 1

प्रश्न 4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

( क ) नव-मार्क्सवादी ढाँचा

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-2, पृष्ठ-12, 'नव-मार्क्सवादी ढाँचा'

( ख ) कानून की अवशिष्ट शक्ति

उत्तर-संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं संसद दोनों को अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, जो कि तीन सूचियों में से भिन्न विषयों पर कानून बना सकती हैं। अवशिष्ट शक्तियों को किसी भी विषय में सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। अवशिष्ट विषय किसी भी नए विषय को सीखने का अधिकार या शक्ति है। भारतीय संविधान ने संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार केंद्र और भारत के विभिन्न राज्यों की शक्तियों को विभाजित किया है। भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ शामिल हैं-संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में मौजूद विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है।

इसी प्रकार भारत के विभिन्न राज्यों की सरकार को भारत के संविधान की राज्य सूची में विविध विषयों के आधार पर ही कानून बनाने का अधिकार लिखा गया है। वर्तमान में, ऐसे 61 विषय पर आधारित विभिन्न राज्यों की सरकार भारत के संविधान द्वारा अनुमोदित के कानून बनाए जा सकते हैं। इन दो अधिकारों के अलावा, जो भारत के केंद्र और राज्य के लिए अलग-अलग विषयों की मांग करते हैं और उन्हें अलग-अलग विषय मिलते हैं, यदि स्थिति के अनुसार कोई अन्य नीति बनाने की आवश्यकता होती है तो ऐसे कानून भारत के केंद्र सरकार द्वारा बनाए जा सकते हैं। भारत की केंद्र सरकार द्वारा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के आधार पर बनाई गई शक्तियों को अविभाज्य शक्तियों के रूप में जाना जाता है।

## भाग-2

प्रश्न 5. 1960 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत के दौरान राज्य स्तरीय नेतृत्व के विकास का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-11, पृष्ठ-106, प्रश्न 2

प्रश्न 6. पूर्वोत्तर भारत में जातीय राजनीति की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-13, पृष्ठ-130, प्रश्न 4

प्रश्न 7. भारतीय जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण पर चर्चा कीजिए।

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-14, पृष्ठ-139, प्रश्न 2

प्रश्न 8. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए-

( क ) विकास का केरल मॉडल

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-7, पृष्ठ-64, 'केरल मॉडल'

( ख ) द्विदलीय प्रणाली

उत्तर-संदर्भ-देखें-अध्याय-9, पृष्ठ-84, 'राज्यों में द्विदलीय प्रणाली'

# **Sample Preview of The Chapter**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# भारत में राज्य की राजनीति ( State Politics in India )

## परिचय ( Introduction )

## भारत में राज्य राजनीति का विकास ( Development of State Politics in India )



### परिचय

भारत में स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान राज्य की राजनीति का विकास एक विशेष रूप में हुआ। राज्यों की पहचान 1956 में भारतीय संघ के पुनर्गठित होने के पश्चात् पहली बार बनी। इन्हें मुख्य रूप से चार श्रेणियों में बाँटा गया—ए.बी.सी. व डी। 1950 तथा 1960 के दशकों में अनेक राज्यों में निराशाजनक घटनाओं के परिणामस्वरूप राजनीति अध्ययन के विशेषज्ञ विभिन्न राज्यों की राजनीति के अध्ययन के लिए प्रेरित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही राज्य की राजनीति में विशेष परिवर्तन हुए हैं। 1960 के दशक से लेकर आज तक कई बार केंद्र और राज्यों ने मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई है तथा कई अवसरों पर राज्य स्तरीय राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को प्रभावित करते हैं। 1976 में प्रकाशित इकबाल नारायण की पुस्तक के बाद से राज्यों की राजनीति पर बहुत से शोध प्रकाशित हुए हैं, जिनमें विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया है, जैसे—दलित, ओबीसी सामाजिक आंदोलन, राज्य स्तर के नेता तथा राजनीतिक दल, चुनाव आदि। इनके अलावा और भी अन्य मुद्दे इसमें सम्मिलित हैं। कुछ शोध कार्य एक या उससे अधिक राज्यों में राजनीति का अध्ययन करते हैं तथा कुछ विभिन्न राज्यों में राजनीति का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। 1980 के दशक तक जाति, धर्म, क्षेत्र तथा भाषा के आधार पर पहचान की राजनीति की उत्पत्ति हुई तथा इसके साथ ही कुछ नए नेताओं का उदय भी हुआ, जिनका आधार क्षेत्रीय पहचान थी। इसके पश्चात् भूमंडलीकरण ने राष्ट्र-राज्य राजनीति की दिशा का परिवर्तन कर दिया और उसने राज्यों को केंद्रीय आधार पर उभरने का अवसर प्रदान किया।

### अध्याय का विहंगावलोकन

#### राज्य राजनीति 1950 से 1960 के दशक

आजादी के बाद पहले दो दशकों तक राज्य की राजनीति का विकास केंद्र के प्रभाव में हुआ, जिसने राष्ट्र निर्माण की जरूरत पर जोर दिया। इस काल के दौरान नेहरू जी का विकास मॉडल एवं भारत की राजनीति पर कांग्रेस दल का वर्चस्व बना रहा। भारतीय राजनीति में केंद्र सरकार का अधिक प्रभाव था, जबकि राज्य की राजनीति द्वितीय स्थान पर आती थी। राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को केंद्र के निर्देशानुसार लागू किया, जो कि राष्ट्र निर्माण से संबंधित थीं। इनमें मुख्य थे—भूमि सुधार, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि। केंद्र में तथा कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी का ही शासन था। कांग्रेस के अंदर कई गुट थे, जो राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेसी गुटों के अनुबंध थे। इनका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाए रखना था। राज्यों तथा केंद्र में एक ही दल की प्रभुसत्ता होने के कारण राज्यों और केंद्र में राजनीति का स्वरूप एक जैसा ही दिखाई पड़ता था।

उस समय राज्य की राजनीति में आपसी मतभेद भी बने रहे, जिनके परिणामस्वरूप राजनीति के मुख्य स्वरूप को चुनौती दी गई। यह स्वरूप था—कांग्रेस का राज्यों में प्रभुत्व तथा क्षेत्रीय दलों की प्रभावहीन स्थिति। आजादी के कुछ वर्षों के अंदर ही उत्तर-पूर्व भारत में नागा और मिजो विद्रोह शुरू हो गए। जम्मू और कश्मीर में जनमत संग्रह फ्रंट आंदोलन शुरू हो गया तथा दक्षिण भारत में भी राज्यों के पुनर्गठन की माँग तीव्र हो गई। कांग्रेस से अलग राजनीतिक दलों ने राज्यों की राजनीति में इस समय के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई। इन्होंने अलग-अलग राज्यों में अपने दल बनाए और कांग्रेस के विरुद्ध विभिन्न मुद्दों पर लोगों को एकजुट किया,



2 / NEERAJ : भारत में राज्य की राजनीति

जैसे—उत्तर भारतीय राज्य में जनसंघ, केरल और पश्चिम बंगाल में समाजवादी और वामपंथियों ने पंजाब में अकाली दल बनाया। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में नृजातीय आंदोलन भी शुरू हुए, जिनकी अलग-अलग प्रकार की माँगें थीं, जैसे—महाराष्ट्र में दलित पैथर, उत्तरी भारत में आर.एस.एस.ए, तमिलनाडु में हिंदी भाषा को लागू करने का विरोध किया गया, मद्रास तमिलनाडु के अलग-अलग होने की माँग की गई। राजस्थान व गुजरात में रूढ़िवादी दलों, जैसे—स्वतंत्र पार्टी ने कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती दी।

सेलिग हेरिसन ने इन घटनाओं के कारण ही 1950 के दशक को सबसे खतरनाक दशक कहा था। कांग्रेस के अंदर भी मतभेद कम नहीं थे। इसमें गुटबंदी के द्वारा नेताओं ने अपना-अपना सामाजिक आधार बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस के सदस्य होते हुए भी उन्होंने अपने-अपने राज्यों में अपने सामाजिक आधार को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण कांग्रेस में विभिन्न गुटों के नेताओं में मतभेद शुरू हो गए। कांग्रेस नेता चरण सिंह इसका उपयुक्त उदाहरण हैं, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए निम्न जातियों और पिछड़े वर्गों के साथ मिलकर अपने लिए एक आधार बना लिया था। उत्तर भारत में कांग्रेस के विभाजन तथा उत्तर भारतीय राज्यों की राजनीति में एक प्रभावशाली क्षेत्रीय और ग्रामीण शक्ति के उद्भव के परिणामस्वरूप वहाँ की राज्यों की राजनीति में परिवर्तन देखने को मिला, जिसकी अभिव्यक्ति 1967 के आम चुनावों में कांग्रेस की हार के रूप में सामने आई। 1969 में गठबंधन सरकार की स्थापना हुई, जिसने भारत संघ के राज्यों की राजनीति में एक नई प्रवृत्ति को जन्म दिया।

**क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और राज्य राजनीति : 1970 का दशक**

1960 और 1970 के दशकों में जवाहरलाल नेहरू के निधन और इंदिरा गांधी द्वारा सत्ता संभालने के बाद व्यक्ति आधारित राजनीति का उदय हुआ। इस दशक के अंत तक राज्य की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग उन ग्रामीण क्षेत्रों में उदय हुआ, जिनमें हरित क्रांति आई थी, जैसे कि हरियाणा और पंजाब में जाट, बिहार में यादव एवं कुर्मी, आंध्र प्रदेश में काम्मा और रेडी तथा कर्नाटक में वोकालिगा और लिंगायत समुदायों के किसान। चरण सिंह ने अपना ध्यान कृषि व्यवस्था पर केंद्रित किया तथा भारतीय क्रांति दल का गठन किया। उन्होंने 1967 से 1987 तक उत्तर भारत की राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखा। उन्हीं को देखते हुए कई अन्य राज्यों में क्षेत्रीय और खेतिहर वर्ग के मजबूत सामाजिक आधार वाले नेताओं का भी उदय हुआ, जिन्होंने अपना ध्यान क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित किया तथा केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार की माँग की।

इस समय कांग्रेस पर सवाल खड़े किए जाने लगे तथा केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की माँग की शुरुआत हुई। क्षेत्रीय नेताओं तथा राजनीतिक पार्टियों के मध्य समन्वय हुआ। इनमें से कुछ नेता राष्ट्रीय स्तर के नेता भी बन गए। आपातकाल के दौरान बहुत-से राज्यों और राष्ट्रीय नेता एवं दल कांग्रेस के विरोध में एकजुट हो

गए। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों ने मिलकर जनता पार्टी का निर्माण किया और केंद्र तथा राज्यों में अपनी सरकार बनाई। जनता पार्टी की सरकार ने जनता के लिए बहुत-सी योजनाओं को लागू किया, जिनका प्रभाव राज्य की राजनीति पर पड़ा। मंडल आयोग की नियुक्ति तथा बिहार और उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण की शुरुआत करने से राज्य और राष्ट्रीय राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन राजनीतिक दलों ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस को तो चुनौती दी ही, साथ ही राज्य संबंधों में और मजबूत स्थान की माँग भी की, जिसके परिणामस्वरूप 1983 में केंद्र-राज्य संबंधों में संशोधन हेतु सरकारिया आयोग का गठन किया गया। 1970 के दशक में जेपी आंदोलन और गुजरात आंदोलन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व को चुनौती दी। इस राजनीतिक असंतोष के कारण ही इंदिरा गांधी को 20 महीने के लिए आपातकाल लगाना पड़ा, जिसके बाद क्षेत्रीय नेताओं, जैसे—चरण सिंह राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में आ गए।

**राज्य राजनीति : 1980 के दशक से**

**पहचान की राजनीति का उदय**

1980 के दशक के बाद के घटनाक्रम जैसे कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गठबंधन की राजनीति की बारंबारता, भूमंडलीकरण, नई पीढ़ी के नेतृत्व का उदय, जातीयता पर आधारित अनेक पहचानों की गतिविधियाँ, किसान आंदोलन, उत्तर-पूर्वी राज्यों, पंजाब तथा जम्मू एवं कश्मीर में विद्रोह तथा स्वायत्तता आंदोलन आदि ने भारत की राजनीति में बहुत-से बदलाव किए। हालांकि, सभी घटनाएँ मुख्य रूप से राज्य राजनीति का ही परिणाम थीं, किंतु इनके विशिष्ट लक्षण पहले के समय की तुलना में बिल्कुल अलग थे। उत्तर भारत में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के रूप में दलित राजनीति में आए तथा पिछड़ा वर्ग जनता दल के रूप में राजनीति में उभरा। बिहार और उत्तर प्रदेश में विभिन्न जातियों के गैर-राजनीतिक मोर्चों के परिणामस्वरूप राज्य राजनीति में और नए आयाम शामिल हुए। इस दौरान अमीर किसान का उद्भव हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भारतीय किसान यूनियन, महाराष्ट्र में शेतकारी संगठन, गुजरात में खेदयूत समाज और कर्नाटक में राज्य रायत संघ का उदय हुआ। इसमें भी 1970 के दशक और 1980 के दशक के रुझानों में भिन्नता थी। 1970 के दशक में किसानों की उत्पत्ति हरित क्रांति और भूमि सुधार के कारण थी, जो सत्ता में अपनी भागीदारी की इच्छा रखते थे। वही 1980 के दशक में कृषकों के पास बाजार अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे थे। नई सामाजिक शक्तियों ने विभिन्न राज्यों में कई प्रकार की माँगें उत्पन्न कीं, इनमें प्रमुख थीं—आरक्षण के मुद्दे, नए राज्यों के सृजन की माँग तथा केंद्र से राज्य तक संसाधनों का अधिक आवंटन।

**भूमंडलीकरण का प्रभाव**

राज्य की राजनीति ने बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंत में एक नया परिवर्तन देखा। भूमंडलीकरण ने एक तरफ केंद्र की स्थिति को कमजोर कर दिया, तो दूसरी तरफ इससे राज्य

राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय शक्तियों की भागीदारी बढ़ गई। सभी राज्यों पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रभाव एक जैसा नहीं पड़ा। कुछ ने इसका उचित लाभ उठाया, किंतु कुछ इससे वंचित रह गए। सही अर्थों में उदारीकरण के कारण राज्यों के बीच निवेश की माँग करने के लिए प्रतिस्पर्धा हुई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भूमंडलीकरण ने राज्यों में असमानता उत्पन्न की है, जिसके कारण कुछ राज्यों का विकास अधिक हो गया, जबकि कुछ राज्य अधिक पिछड़ गए। आज राज्यों की स्थिति यह है कि वह प्रत्यक्ष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय डोनर्स के साथ समझौता कर सकते हैं तथा विभिन्न एजेंसियों के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से समझौता कर सकते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत रहती है। भूमंडलीकरण के परिणामस्वरूप अंतरराज्यीय संस्थाओं का पतन भी हुआ। सेज का मत है कि अंतर शासकीय सहयोग ने अंतर अधिकार क्षेत्र प्रतियोगिता में वृद्धि कर दी है। दलीय व्यवस्था में भी भूमंडलीकरण के दौरान परिवर्तन दिखाई दिए।

ज्यादातर राज्यों में दो या दो से अधिक दलों का उदय एक प्रमुख दल के रूप में हुआ है। राज्य स्तरीय दलों का दबाव किसी विशिष्ट क्षेत्र, धर्म या जाति की ओर होता है, जिनका प्रभाव चुनावों पर पड़ता है और गठबंधन करके सरकार बनाई जाती हैं। इसका मुख्य उदाहरण—बहुजन समाज पार्टी है, जिसका प्रमुख आधार उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा मध्य प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी, अकाली दल राष्ट्रीय लोकदल, उत्तर भारतीय राज्यों में बीजू जनता दल, पूर्वी भारत में तथा दक्षिण भारत में तेलुगू देशम पार्टी, ए.आई.ए.डी.एम.के. तथा डी.एम.के., महाराष्ट्र में शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी इत्यादि। राजनीतिक दलों की भूमिका चुनाव में लोगों को एकजुट करने की होती है, किंतु नई शक्तियों के उदय से दलित पिछड़ा वर्ग गैर-चुनावी लामबंदी को बढ़ावा मिला है। इनका प्रभाव चुनावों पर भी पड़ता है। राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों का प्रसार किसी एक शक्ति या दल को राज्य की राजनीति पर हावी नहीं होने देता, किंतु वे सत्ता में अपना हिस्सा चाहते हैं।

### विद्रोह एवं राज्य राजनीति

राज्य की राजनीति पर उग्रवाद का बहुत प्रभाव पड़ता है, जैसा कि 1980 के दशक में पंजाब, उत्तर-पूर्व भारत तथा जम्मू और कश्मीर में देखा गया। इन घटनाक्रमों का प्रभाव न केवल राज्यों की राजनीति पर पड़ा, बल्कि इसका गंभीर प्रभाव देश की राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ा। उग्रवाद की समस्याओं का संबंध विकास, अंतरराज्यीय संबंधों, स्वायत्तता या आत्मनिर्णय के मुद्दों से जुड़ा हुआ है। उग्रवाद की शुरुआत राष्ट्र-राज्य या उसके प्रतिनिधियों के बीच होती है, किंतु अनेक उदाहरणों में यह नृजातीय दंगों में बदल जाती है तथा ये नृजातीय दंगे विभिन्न जातीय समूहों के मध्य होते हैं। भारत के समक्ष विद्रोह की समस्या कोई नई नहीं है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद ही ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 1970 के दशक में जहाँ एक ओर राज्य स्तर के नेताओं तथा दलों के उदय ने प्रमुख पार्टी प्रणाली को चुनौती दी, वहीं

दूसरी ओर विद्रोही आंदोलनों ने केंद्र के समांगीकरण वाले दृष्टिकोण पर प्रश्नचिह्न लगाया। समांगीकरण का दृष्टिकोण राष्ट्र निर्माण पर बल देता है तथा इसने संघीय निर्माण दृष्टिकोण को वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया। कुछ स्थितियों में विद्रोह स्वायत्तता या बाहर के लोगों के विरुद्ध असहयोग का सह-उत्पादक होता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नए समूह स्वायत्तता या आत्मनिर्णय की माँग करते हैं, जैसे—उत्तर-पूर्व में असम में उल्फा, बोडो, कार्वी लोग आसु आंदोलन में सहभागी थे। इन समूहों को लगा कि इनकी उपेक्षा की गई है और इसलिए उन्होंने भारतीय संघ में रहकर स्वायत्तता की माँग की।

### बोध प्रश्न

**प्रश्न 1. स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम दो दशकों में भारतीय राज्य की राजनीति के प्रमुख लक्षण कौन-कौन से थे?**

उत्तर—स्वतंत्रता के पश्चात् प्रथम दो दशकों में राज्यीय राजनीति केन्द्र के प्रभाव में ही अंकुरित हुई, जिसने भारत में राष्ट्र राज्य निर्माण के अनुशीलन पर ध्यान केन्द्रित किया। इस अवधि में विकास के नेहरूवादी आदर्श और कांग्रेस के एक-दलीय प्रभुत्व ने ही भारत में राजनीति को अभिव्यक्ति प्रदान की। राज्यीय राजनीति मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजनीति का ही प्रतिरूप थी। केन्द्र सरकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक प्रभावशाली स्थिति रखती थी, जिसमें राज्यीय राजनीति को दूसरा स्थान प्राप्त था। केन्द्र के दिशानिर्देश पर राज्य सरकारों ने अनेक कदम उठाए, ताकि राष्ट्र निर्माण की दिशा में योगदान दिया जा सके, जैसे—भूमि सुधार और सामुदायिक विकास-कार्यक्रम। केन्द्र में और बहुत-से राज्यों में सत्ता कांग्रेस पार्टी के पास थी। राज्यों में साम्प्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करती कांग्रेस के भीतर विभिन्न स्वार्थी गुट राष्ट्रीय स्तर पर स्वार्थी दल नेतृत्व के अनुबंध थे। यह तथ्य कि केन्द्र व अनेक राज्यों में प्रबल दल का ही बोलबाला रहता था, ने इसके साथ ही यह मान लिया कि राज्यों व केन्द्र में राजनीति का एक सर्वमान्य प्रतिमान है। राज्यपाल, केन्द्र में अनुकूल सरकारों की यथा नियुक्तियों के रूप में, कुछेक को छोड़कर, निर्विवादात्मक ही रहते थे। निस्संदेह, यह एक प्रमुख पैटर्न था, परन्तु इसके साथ ही राज्यीय राजनीति के भीतर एक ही समय में असम्मत प्रतिमान भी सामने आए। इस घटनाक्रम ने राजनीति के प्रमुख प्रतिमान को चुनौती दी, यथा—कांग्रेस की प्रमुख स्थिति और राज्यीय राजनीति की गौण अथवा द्वितीयक स्थिति थी।

**प्रश्न 2. कांग्रेस के प्रभुत्व या एकदलीय व्यवस्था के वर्चस्व का पतन क्यों हुआ?**

उत्तर—1950 से 1960 के दशक के बीच राजनीति पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व बना हुआ था, किंतु कांग्रेस का सिंहासन कायम नहीं रह पाया। जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में कांग्रेस नाकाम रही और कुछ ही वर्षों के अंदर उत्तर-पूर्व भारत में नागा और मिजो विद्रोह शुरू हो गए। जम्मू और कश्मीर में जनमत

4 / NEERAJ : भारत में राज्य की राजनीति

संग्रह फ्रंट आंदोलन शुरू हो गया तथा दक्षिण भारत में भी राज्यों के पुनर्गठन की माँग शुरू हो गई। यहाँ तक कि कांग्रेस से भिन्न वैचारिक धारणा रखने वाले दलों ने भी राज्यों की राजनीति में इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल व पश्चिम बंगाल में समाजवादियों व वामपंथियों ने मिलकर, उत्तर भारतीय राज्यों में जनसंघ ने और पंजाब में अकाली दल ने लोगों को कांग्रेस के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर संगठित किया।

महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में आर.पी.आई. के नेतृत्व में दलित आन्दोलन और महाराष्ट्र में दलित पैथर; उत्तर भारत में जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उनके संबद्ध दलों के गौ-रक्षा आन्दोलन; हिन्दी भाषा के प्रसार हेतु समाजवादी आन्दोलन तथा तमिलनाडु में हिन्दी भाषा थोपे जाने का विरोध व भारत से मद्रास/तमिलनाडु के संबंध-विच्छेद हेतु माँग राज्यीय राजनीति के प्रतिमानों हेतु नृजातीय आयामों के आरंभिक उदाहरण हैं। कांग्रेस के आधिपत्य को गुजरात व राजस्थान में स्वतंत्र जैसी रूढ़िवादी पार्टियों द्वारा भी चुनौती दी गई, अर्थात् यह वह समय था, जब कांग्रेस के प्रति चारों तरफ असंतोष उत्पन्न हो गया। यहाँ तक कि कांग्रेस के भीतर स्वार्थी गुटों के नेतागण अपने-अपने सामाजिक आधार तैयार करने में पीछे नहीं रहे। कांग्रेस के सदस्य रहते हुए भी उन्होंने अपने-अपने राज्यों में स्वयं के आधारों को मजबूत किया। इसके परिणामस्वरूप नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का आदान-प्रदान शुरू हो गया।

**प्रश्न 3. 1970 के दौरान राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषताओं की पहचान बताइए।**

उत्तर—साठ व सत्तर के दशक में राज्यीय राजनीति के प्रतिमानों में परिवर्तन जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात् हुए। साठ और सत्तर के दशक के बीच राज्यीय राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षणों में एक था—ग्रामीण धनाढ्यों अथवा कुलों का उदय, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ हरित क्रांति का प्रभाव था। सर्वाधिक प्रासंगिक उदाहरण हैं—उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब में जाट, बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश में यादव और कुर्मी, आन्ध्र प्रदेश में रेड्डी व काम्मा, कर्नाटक में वोकालिंग्गा और लिंगायत आदि। कृषिक कार्यवली पर विशेषकर ध्यान आकृष्ट करते हुए चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल का गठन किया। उन्होंने दो दशकों (1967-1987) की अवधि में बिहार व हरियाणा में राज्य स्तरीय नेताओं को साथ लेकर उत्तर भारत की राजनीति पर अपना प्रभाव बनाए रखा। उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर कृषि वर्गों के बीच प्रबल सामाजिक आधारों को लेकर बड़ी संख्या में राज्यों में सशक्त क्षेत्रीय नेताओं का उद्गमन हुआ। इन नेताओं व पार्टियों ने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया और केन्द्र-राज्य संबंधों में सुधार की माँग की। राज्यपाल, जो कि प्रभावी दल, यथा कांग्रेस के प्रति अनुकूल माना जाता था, की भूमिका पर संदेह किया जाने लगा और केन्द्र-राज्य संबंधों में परिवर्तन की माँग की।

क्षेत्रीय नेताओं व राजनीतिक दलों के बीच समन्वय हो गया और इनमें से कुछ नेताओं ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की पदवी

प्राप्त कर ली। इन नेताओं ने अपनी शक्ति क्षेत्रीय/राज्यीय राजनीति (राष्ट्रीय राजनीति की योग्यता प्राप्त कर लेने के बावजूद) से ही निष्कर्षित की और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का नेतृत्व किया। आपातकाल लागू किए जाने के कारण राज्यीय व राष्ट्रीय नेता व दलों को अवसर मिल गया और उन्होंने मिलकर प्रभुत्व वाली कांग्रेस का विरोध किया। जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकारों ने केन्द्र व राज्यों, दोनों में कुछ कदम उठाए, जिनमें राजनीति की गूँज सुनाई दी। मंडल आयोग की नियुक्ति और बिहार व उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किए जाने वाली नई प्रवृत्तियाँ पैदा कीं, जो राज्यीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण थीं। साठ के दशकांत से अस्सी के दशकारंभ तक केन्द्र-राज्य संबंधों को सुधारने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठकें, राजमन्मार आयोग की नियुक्ति, पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा का संकल्प तथा 1983 में सरकारिया आयोग की नियुक्ति आदि क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों के बढ़ते महत्त्व के सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण रहे।

**प्रश्न 4. भारत में राज्य की राजनीति पर पहचान के प्रभाव को समझाइए।**

उत्तर—अस्सी के दशक के बाद की घटनाओं ने भारत में राज्यीय राजनीति के बदलते दौर और राष्ट्रीय राजनीति में राज्यों की भूमिका में और अधिक योगदान दिया। यह घटनाक्रम इस प्रकार था—राष्ट्रीय एवं राज्यीय स्तरों पर गठबंधन राजनीति की बारंबारता; भूमण्डलीकरण; नेतृत्व की पुनः एक और पीढ़ी का उद्गमन; नृजातीय, यथा—जाति (दलित व पिछड़े वर्ग), जनजाति, भाषा आदि पर आधारित बहुत-सी पहचानों के अधिकार की माँग; किसानों के आन्दोलन; उत्तरी-पूर्व, जम्मू-कश्मीर व पंजाब में विप्लव तथा स्वायत्तता आन्दोलन। विभिन्न सामाजिक समूहों के आन्दोलनों को नव सामाजिक आन्दोलन के रूप में जाना जाने लगा है। हालांकि, ये घटनाएँ मुख्य तौर पर राज्यीय राजनीति के परिणामस्वरूप हुईं, फिर भी पूर्व काल के मुकाबले ये लक्षण भिन्न थे। हाल के दिनों में उत्तर में दलितों व पिछड़े वर्गों के अधिकारों की माँगों ने सिर्फ पहले दक्षिण में इसी प्रकार के दावों वाली राजनीति में इजाफा किया है। बसपा के रूप में उत्तर भारत में दलितों के, बिहार व उत्तर प्रदेश में जनता दलों के विभिन्न अवतरणों के रूप में पिछड़े वर्गों के और विभिन्न जातियों के साथ-साथ धर्म से जुड़े गैर-पार्टी मोर्चों के राजनीतिकरण ने भारत में राज्यीय राजनीति को नए आयाम प्रदान किए हैं।

इस अवधि में उत्तर प्रदेश व पंजाब में भारतीय किसान यूनियनों (भा.कि.यू.), महाराष्ट्र में 'शेतकारी संगठन', गुजरात में 'खेदयूत समाज' तथा कर्नाटक में 'कर्नाटक राज्य रायत संघ' के रूप में धनाढ्य किसानों का उद्गमन देखा गया। 1970 के दशक में जो कृषक समूह उत्पन्न हुए, उन्होंने हरित क्रांति व भूमि सुधारों के परिणामस्वरूप मुख्य तौर पर राजनीतिक सत्ता में भागीदारी एवं कृषि उत्पादों के लिए व्यापार संबंधी अनुकूल शर्तों के लिए